

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,  
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. श्री मुकेश वर्मा,  
अधिवक्ता,  
50-लायर्स चैम्बर्स,  
मा0 उच्चतम न्यायालय,  
नई दिल्ली-110001

3. श्री प्रतीक द्विवेदी,  
अधिवक्ता,  
चैम्बर नं0-53,  
ओल्ड लायर्स चैम्बर्स,  
मा0 उच्चतम न्यायालय,  
नई दिल्ली-110001

2. श्री विश्वजीत सिंह,  
अधिवक्ता,  
112-एम0सी0 शीतलवड चैम्बर्स,  
भगवानदास रोड,  
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया,  
नई दिल्ली-110001

4. श्री अमित कुमार सिंह,  
अधिवक्ता,  
311-रेगलिया हाईट्स  
शिप्रा सन सिटी,  
नोयडा।

न्याय अनुभाग:1

देहरादून : दिनांक 11 जुलाई, 2012

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु स्थायी अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको स्थायी अधिवक्ता के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया है।

2- उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3- आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-68/XXXVI(1)/2010-43-एक(1)/03 दिनांक 25-03-2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ कि यदि सहमत हों तो कृपया अपनी लिखित सहमति उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)  
प्रमुख सचिव

संख्या: 191(1)/XXXVI(1)/2012-75/2007 टी0सी0 तदुदिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 3- महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 4- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिव।

क्रमशः.....2